



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2007/वैशाख 21, 1929

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2007/VAISAKHA 21, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2007

सं. 67/2007—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 343(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, जनवादी गणराज्य चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मूलतः उद्गमित या वहाँ से निर्यातित विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न विट्रीफाइड और पोर्सिलेन टाइलों जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 73/2003—सीमाशुल्क तारीख 1 मई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) सा.का.नि. 376(अ), तारीख 1 मई, 2003, के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया है, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/17/2006—डीजीएडी, तारीख 30 अप्रैल, 2007 के तहत पहली अनुसूची के शीर्ष 6907 अथवा 6908 के अंतर्गत आती हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 के 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995, (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में निर्णयक समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2003—सीमाशुल्क तारीख 1 मई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) सा.का.नि. 376(अ), तारीख 1 मई, 2003, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् और परंतुक से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विख्याति न किया जाये, 1 मई, 2008 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी”।

[फा. सं. 354/214/2001-टी.आर.यू (भाग-III)]

एस. बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2007

No. 67/2007-CUSTOMS

G.S.R. 343(E).—Whereas, the designated authority *vide* Notification No. 15/17/2006-DGAD, dated the 30th April, 2007, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 30th April, 2007, has initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles, falling under headings 6907 or 6908 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China and United Arab Emirates (UAE), imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.73/2003-Customs, dated the 1st May, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 376(E), dated the 1st May, 2003, and has requested for extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of its expiry, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.73/2003-Customs, dated the 1st May, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 376 (E), dated the 1st May, 2003, namely:—

In the said notification, after the paragraph 2 and before the first proviso, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“This notification shall remain in force upto and inclusive of the 1st May, 2008, unless the notification is revoked earlier”.

[F. No. 354/214/2001-TRU (Pt.-III)]

SONAL BAJAJ, Under Secy.